बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 130

निर्यात की समस्या

मध्यम अवधि में देश की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला एक और वाकया सामने आया है। इस सप्ताह जारी आंकड़ों के मुताबिक निर्यात वृद्धि 41 महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मई में मामूली बढ़ोतरी के बाद जून 2019 में निर्यात सालाना आधार पर 9.7 फीसदी कम हुआ।

बाह्य खाते को लेकर कोई तात्कालिक चिंता नहीं है क्योंकि आयात में भी काफी कमी आई है और इसके चलते व्यापार घाटा कम हुआ है। परंतु यह बात प्रासंगिक नहीं है। दरअसल बात यह है कि निर्यात अब वृद्धि को प्रभावित कर रहा है जबकि एक समय यह आर्थिक विस्तार का इंजन हुआ करता था। पिछले कुछ वर्षों से यही कहानी देखने को मिल रही है। अक्सर कुछ सुधार होने पर आशा का संचार होता है लेकिन अंततः विफलता ही हाथ लगती है। आंकड़ों पर करीबी नजर डालें तो आशावाद की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि निर्यात में गिरावट की एक बड़ी वजह परिशोधित पेट्रोकेमिकल का निर्यात कम होना है। उनके मुताबिक यह अस्थायी हो सकता है। दो बड़ी रिफाइनरी-रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी और मंगलूरु की सरकारी रिफाइनरी को इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए बंद भी किया गया ताकि रखरखाव का काम किया जा सके।

बहरहाल, केवल इससे मंदी को नहीं समझा जा सकता है। गैर तेल निर्यात में 6 फीसदी तक की कमी आई है। उदाहरण के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की निर्यात वृद्धि में निरंतरता का अभाव है और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात जून में 2.65 फीसदी कम हुआ। ध्यान रहे कि गत वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में काफी तेजी नजर आई थी।

इस गिरावट के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल हालात को भी वजह माना जा सकता है। यह सच है कि अमेरिका-चीन व्यापारिक युद्ध को लेकर चिंता का माहौल है। परंतु कई देशों के लिए यह अवसर भी है। उदाहरण के लिए वियतनाम ने वर्ष 2019 के शुरुआती पांच महीनों में 6.7 फीसदी की निर्यात वृद्धि हासिल की है। बांग्लादेश ने गत वित्त वर्ष में वस्त्र निर्यात में दो अंकों में वृद्धि हासिल की जबकि भारतीय वस्त्र निर्यातक संघर्षरत रहे। सन 2014-15 में देश का कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात 40.1 अरब डॉलर का था। 2018-19 में यह महज 40.4 अरब डॉलर रह गया। यह बताता है कि कैसे हम इस श्रम आधारित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी नहीं हो सके।

सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी विभिन्न व्यापारोन्मुखी योजनाएं कारगर नहीं साबित हुई हैं। इनमें क्षेत्रवार पैकेज और आयात पर उच्च शुल्क दर शामिल है। इन सभी ने देश के व्यापारिक और कारोबारी क्षेत्रों को कम प्रतिस्पर्धी बनाया है। इसके अलावा ऋण की कमी और वस्तु एवं सेवा कर के कमजोर क्रियान्वयन ने भी निर्यात वृद्धि को प्रभावित किया है। ऐसे में पहले कदम के रूप में कर प्रक्रियाओं को सहज बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के बजाय सरकार ने कहा है कि निर्यातकों को टैक्स क्रेडिट मुहैया कराने के पहले जांच-परख की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि रिटर्न फाइल करने और रिफंड मिलने के बीच का अंतर और ज्यादा बढ़ेगा। कम मार्जिन वाले निर्यात के लिए यह बड़ी बाधा होगी। कर संबंधी विषय तो कहानी का केवल एक हिस्सा हैं। प्रतिस्पर्धा में आ रही कमी और अधिमूल्यित रुपया भी निर्यात की बुरी हालत के लिए उत्तरदायी हैं। निर्यात की चुनौतियां देश की अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरी को सामने रखती हैं। इन्हें ढांचागत सुधार के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। नई सरकार को इस समस्या को गंभीरतापूर्वक हल करना चाहिए।

विनय सिन्हा

बजट का 'स्वदेशी' राग वैश्विक आकांक्षा में दाग

अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य संरक्षणवादी कदमों से नहीं बल्कि अधिक भूमंडलीकरण से ही हासिल किया जा सकता है। बता रहे हैं श्याम सरन

ऊंची महत्त्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है और भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य स्वागतयोग्य है। यह लक्ष्य हासिल भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी चीजें पहले से मौजूद हैं। भले ही भारत की जनसंख्या लंबे समय तक अपने सर्वाधिक उत्पादक स्वरूप में न रहे लेकिन फिलहाल यह उसी दौर में है। भारत के पास एक विस्तृत एवं अपेक्षाकृत परिष्कृत औद्योगिक आधार एवं गतिशील उद्यमिता है। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जैसे क्षेत्रों का प्रदर्शन विश्वस्तरीय है। भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पास विशाल एवं बढ़ते हुए डेटा संसाधन हैं जो कृत्रिम मेधा (एआई) एवं मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्रों में भी तीव्र विकास कर सकते हैं।

भारतीय बाजार के बड़े आकार का इस्तेमाल न केवल बड़ी विदेशी पूंजी एवं तकनीक के प्रवाह को लुभाने बल्कि व्यापार एवं निवेश की शर्तों को लाभदायक बनाने के लिए भी किया जा सकता है। भारत अपने प्रगति पथ के एक बेहतरीन बिंदु पर खड़ा है। हमें इन संसाधनों का फायदा उठाने के लिए साहसी आर्थिक रणनीति की जरूरत है लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि अवसर की यह खिड़की जल्द ही बंद भी हो जाएगी।

हाल में पेश आम बजट में कई सकारात्मक बातें हैं। निवेश बहाली पर जोर, आधारभूत ढांचे का निर्माण, निर्यात प्रोत्साहन, वित्तीय बाजार के सशक्तीकरण एवं रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। लेकिन एक नीतिगत उद्देश्य के तौर पर आयात प्रतिस्थापन का दोबारा आगमन परेशान करता है। पिछले दो बजट की तरह इस बजट ने भी कई आयात पर शुल्क बढ़ाने का तरीका जारी रखा है। अब तो यह एक प्रवृत्ति बन चुकी है। हम पर वर्ष 1991 से पहले की रणनीति की तरफ खिंचने का खतरा मंडरा रहा है जो आयात प्रतिस्थापन और संरक्षित घरेलू उत्पादन पर आधारित थी। कुछ दूसरे चिंताजनक संकेत भी हैं। इस सदी के पहले दशक में कई मुक्त व्यापार समझौते होने के बाद अब धारणा उनके खिलाफ बन चुकी है। इन समझौतों से भारत के व्यापार की कुल मात्रा में भले ही वृद्धि हुई हो लेकिन उनकी वजह से व्यापार घाटा बढ़ा भी है। आलोचना होती है कि हमारे व्यापार साझेदारों को इन समझौतों से हमारी तुलना में कहीं अधिक लाभ हुआ है। प्रस्तावित क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर हस्ताक्षर करने में भारत की हिचकिचाहट के पीछे भी यही धारणा है। भारत इस समझौते का हिस्सा होने पर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड और आसियान देशों के साथ व्यापक गठजोड़ में शामिल हो जाएगा।

भारत के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच हासिल करना और अपनी कंपनियों के लिए बराबरी का मौका दिए जाने की मांग करना वाजिब है। कुछ मुक्त व्यापार समझौतों की शर्तों की समीक्षा किए जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। एक आयात प्रतिस्थापन रणनीति की तरफ लौटना कोई जवाब नहीं है। कुछ उत्पादों पर चुनिंदा ढंग से शुल्क बढ़ाने के साथ समस्या यह है कि इससे निहित स्वार्थ पैदा होते हैं जिनसे बाद में छुटकारा ले पाना मुश्किल होता है। भारतीय रुपये की विनिमय दर में कमी लाना बेहतर तरीका हो सकता है। इसका भी वही असर हो सकता है जो ऊंचे शुल्क से होगा और दूसरों की तुलना में कुछ उद्योगों को ही तरजीह देने वाले क्षेत्रवार असर के बगैर यह होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों की यह दलील है कि रुपये की कीमत चढ़ी हुई है।

मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में मेरे सहकर्मी वी एस शेषाद्रि के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय उद्योग इन समझौतों को विस्तारित एवं अधिक विविध बाजार पहुंच के साधन से ज्यादा अपने मौजूदा निर्यात के लिए बाजार पहुंच बनाए रखने पर देखते हैं। भारतीय निर्यातक गैर-शुल्क बाधाएं दूर करने या मूल्य-वर्द्धन करने के लिए इन समझौतों में मौजूद प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। जापान के साथ समझौते में भारतीय दवा उद्योग की मदद की प्रतिबद्धता है जिससे जापानी बाजार में भारतीय दवाओं को प्रवेश के पहले पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया से राहत मिल सकती है लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। व्यापक समझ यही है कि भारतीय उद्योग ने मुक्त व्यापार समझौतों के प्रति रक्षात्मक रवैया अपनाया और इसे अपना बाजार फैलाने के मौके के रूप में नहीं देखा। आयात प्रतिस्थापन से इस मनोदशा में बदलाव की संभावना नहीं है। संरक्षणवादी नीतियां अपनाने से भारतीय उद्योग अधिक नहीं बल्कि कम प्रतिस्पर्द्धी बनेगा। यह निर्यात प्रोत्साहन की घोषित नीति के खिलाफ जाएगा। वर्ष 1991 के पहले हमारा अनुभव पुख्ता सबूत देता है कि संरक्षणवाद से खराब गुणवत्ता एवं कमतर सेवा मिलती है क्योंकि उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होते हैं। यह दलील पूरी तरह गलत है कि ऊंचे शुल्क से भारतीय उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्द्धी होने के लिए अधिक वक्त एवं स्थान मिल जाएगा। एक विदेशी निवेशक भी भारत में कम प्रतिस्पर्द्धा होने से यहां पर दोयम दर्जे एवं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचकर खुश होता है। ऐसी स्थिति में उच्च तकनीक वाले उत्पादों एवं सेवाओं के भारतीय बाजार में आने का प्रोत्साहन कम रह जाता है। इसका नतीजा यह होगा कि भारत अपने विशाल बाजार के बावजूद आला दर्जे का निवेश नहीं जुटा पाएगा जो कि मौका गंवाने के समान होगा। विदेशी उधारी के जरिये फंड जुटाने के प्रस्ताव पर भी सावधानी भरा रवैया अपनाने की जरूरत है। सॉवरिन बॉन्ड बेचने से सरकार की देनदारियां उस समय और बढ़ जाएंगी जब रुपये की कीमत गिरेगी। पिछले पांच वर्षों में निर्यात स्थिर रहा है और अगर उसी तरह रहता है तो हमें फिर से भुगतान चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आज निर्यात के खास उपकरणों एवं मध्यवर्ती उत्पादों के आयात पर भी निर्भर होने से आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रोत्साहन में सेंध लगा सकता है।

नरसिंह राव सरकार के पहले दो वर्षों में प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी तैनाती के दौरान मैं कई ऐसी बहसों का गवाह रहा जिनमें आयात प्रतिस्थापन एवं आत्म-निर्भरता की रणनीति को तिलांजलि देने का जिक्र होता था। देश के जाने-माने उद्योगपतियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के लायक न होने से भारतीय उद्योग के खोखला हो जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन वे गलत साबित हुए और भारत उच्च-वृद्धि पथ पर चल पड़ा। ऐसा साहसिक सुधारों और उदारीकरण के लिए उठाए गए कदमों से ही संभव हो सका। इससे भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्द्धी ही बने और वे पहले से स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों का भी सामना करने लायक बन सके। अगर अतीत के इन सबक को हम भूल जाते हैं और 'स्वदेशी' आवरण में चले जाते हैं तो वह दुखद होगा। यह तीव्र विकास दर नहीं धीमी दर का नुस्खा है। इससे न तो पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगी और न ही भारत की बड़ी भू-राजनीतिक अहमियत ही कायम रहेगी। भारत एक अग्रणी शक्ति के रूप में विस्तारित भू-राजनीतिक भूमिका नहीं निभा सकता है। वैश्वीकरण को तकनीक से ताकत मिलती है और हमारी प्राथमिकताओं से परे वह आगे बढ़ेगा। भविष्य उन देशों का ही होगा जो वैश्वीकरण वक्र से आगे रहेंगे और सभी आयामों में विलक्षणता हासिल करने पर जोर देंगे। लेकिन आम बजट में की गई कुछ घोषणाएं इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती हैं।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं और अभी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)

व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र और उसकी सफलता के उदाहरण

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

इस माह के शुरू में जारी आर्थिक समीक्षा में जब पूरा एक हिस्सा व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र को समर्पित किया गया तो यह विषय अचानक चर्चा में आ गया। समीक्षा में बताया गया कि कैसे लोगों की चयन की आजादी बरकरार रखते हुए भी उन्हें वांछित परिणाम की ओर ले जाया जा सकता है। समीक्षा के इस हिस्से में बताया गया कि कैसे स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टि की सफलता के उदाहरण हैं।

इस तकनीक का सबसे सफल इस्तेमाल ब्रिटेन में उस समय किया गया जब सरकार को कर भुगतान में अंतिम समय में हुए इजाफे से निपटना मुश्किल हो रहा था। सरकार द्वारा स्थापित व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टि पर काम करने वाली एक टीम ने लोगों को बार-बार यह याद दिलाने वाले पत्र भेजने शुरू कर दिए कि उनके अधिकांश पड़ोसी पहले ही टैक्स अदा कर चुके हैं। इसके बाद कर चुकता होने के मामलों में अचानक तेजी आई। इस सफलता से उत्साहित ब्रिटेन की सरकार ने ऐसी गतिविधियों का दायरा बढ़ाया: कर भुगतान से लेकर इसे अस्पताल के उन अपॉइंटमेंट्स पर लागू किया गया जिन तक पहुंचने में लोग चूक गए थे।

व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र कुछ और नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक निर्णय लेने के तौर तरीकों का अध्ययन है। इस अध्ययन में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। कई बड़ी कंपनियों के मानव संसाधन व्यवहार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में मानव संसाधन क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर इन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये प्रभावी भी साबित हो रही हैं।

उदाहरण के लिए गूगल ने येल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर यह अध्ययन किया कि व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र कैसे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बेहतरी में काम आ सकता है। यह अध्ययन तब किया गया जब पता चला कि खराब स्वास्थ्य और मोटापा आदि अमेरिकी कंपनियों पर हर वर्ष बहुत गहरा असर डालते हैं। ऐसे में कंपनी ने खानपान के दौरान कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की कि खानेपीने के अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प कौन से हैं? उन्होंने स्वास्थ्यवर्धक भोजन को नुकसानदेह खाने से पहले रखना शुरू किया ताकि कर्मचारी पौष्टिक खाना खाने के लिए प्रेरित हों।

गूगल और येल के शोधकर्ताओं ने कम लोकप्रिय सब्जियों का प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें बेहतर बताना शुरू किया। इन सब्जियों को रंगीन कागज में कुछ दिलचस्प तथ्यों के साथ रखना शुरू किया गया। इससे इन सब्जियों की खपत में 74 फीसदी तक इजाफा हुआ।

अन्य कंपनियों ने भी इससे मिलते जुलते कदम उठाए और उन्होंने खाने के साथ उससे मिलने वाली कैलरी की जानकारी देना शुरू किया। इससे उन लोगों को मदद मिली जो अपने वजन पर ध्यान दे रहे थे या जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक खाने की तलाश में थे।

व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र 2008 में नज: इंप्रूविंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ, वेल्थ ऐंड हैपिनेस नामक बेस्टसेलिंग किताब से अस्तित्व में आया। यह किताब रिचर्ड एच टालर और विधिक विद्वान कास आर सनस्टेन ने मिलकर लिखी थी। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी चीज का कार्य के प्रति व्यवहार इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके सामने चीजें किस प्रकार पेश की जाती हैं।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अगर कार्यालय की सीढ़ियां अच्छी दिखती हों और बीच में स्थित हों तो लोग कोने में लगे एलिवेटर की तुलना में उनका इस्तेमाल पसंद करते हैं। यह न केवल उत्साहवर्धक कवायद है बल्कि यह अधिक खुली कार्य संस्कृति पैदा करती है।

ऐसे में व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र भी मानव संसाधन के लिए ऐसा अहम क्षेत्र है जिसका प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। इससे कंपनी को लोगों की नियुक्ति में बेहतर निर्णय करने में मदद मिलेगी और लोग भी अपने काम से जुड़ाव महसूस करेंगे। कई प्रमुख कंपनियों ने इसके सिद्धांतों को अपने मानव संसाधन व्यवहार में अपनाया है।

व्यवहार विज्ञान ने कंपनियों को यह अंतर्दृष्टि भी प्रदान की है कि वे अपने कर्मचारियों के दिमाग को सही तरीके से कैसे पढ़ें? उदाहरण के लिए पाया गया कि किसी बात को बार-बार दोहराने से कर्मचारी बेहतर ढंग से सीखते हैं। ऐसे में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय कई कंपनियों ने हर आधे घंटे में या सत्र के अंत में या फिर कुछ महीने बाद याद दिलाने की कवायद को शामिल किया। कुछ कर्मचारियों को यह खिझाने वाला लग सकता है लेकिन कई अन्य के लिए यह उपयोगी है। इससे प्रबंधन को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में सटीक प्रतिपुष्टि मिलती है।

इसमें यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि संदेश कैसे भेजा जाता है? उदाहरण के लिए दबाव डालने वाली बातों की जगह अगर छोटे और सहज संदेशों के माध्यम से कोई बात याद दिलाई जाए तो उसका प्रभाव काफी अधिक होता है। यानी अगर आप किसी हस्तक्षेप के बिना लोगों के दिमाग में कोई बात डालते हैं तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से असर करती है।

टालर ने तीन सिद्धांत प्रस्तुत किए और कहा कि प्रेरित करने की यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसे भ्रामक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बाहर निकलने का भी सहज विकल्प होना चाहिए और यह मानने की वजह होनी चाहिए कि व्यवहार को प्रोत्साहन देकर लोगों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने अपने काम को तीन शब्दों में समेटा: इसे आसान बनाइए। दिग्गज कंपनियां इसका बाइबल की तरह अनुसरण करती हैं।

कानाफूसी

बिना जमीन कैसी सड़क?

मंगलवार का दिन केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के लिए खुशियां लेकर आया। उस दिन लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने उनकी तारीफ की। सबसे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व सूचना संपन्न और नवाचारी है। इसके बाद रिवॉल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि गडकरी के अनुकरणीय प्रदर्शन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए वह उन 21 कटौती प्रस्तावों को वापस ले रहे हैं जो उन्होंने अनुदान मांग के खिलाफ पेश किए थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुदीप बंद्योपाध्याय मंत्री की योजनाओं से प्रभावित नहीं नजर आए। मंत्री द्वारा वर्णित योजनाओं में शहरों में दोमंजिला बसें चलाने की बात शामिल है। बंद्योपाध्याय ने उन्हें सपनों का सौदागर बता दिया। उन्होंने यह मांग भी की कि देश के पूर्वी इलाकों में और अधिक सड़कों का निर्माण किया जाए। गडकरी ने जवाबी हमला बोला और कहा कि सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में अगर किसी प्रांत में सबसे अधिक परेशानी होती है तो वह है पश्चिम बंगाल।

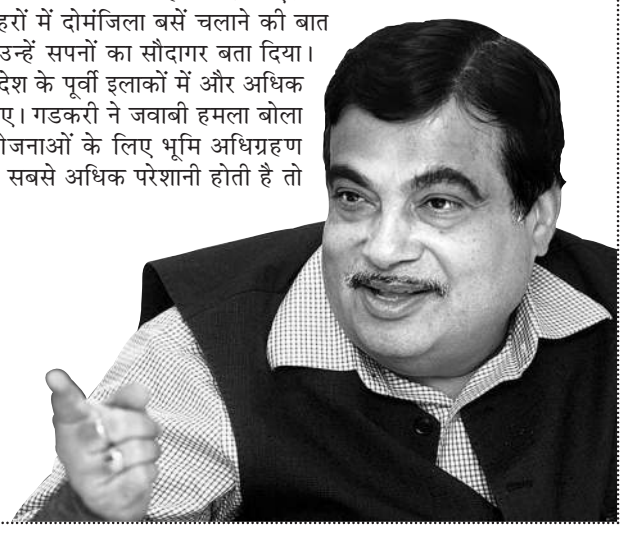

आपका पक्ष

रासायनिक खेती चिंता का विषय

हाल में भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य उत्पाद कंपनियों को प्रसंस्कृत किए गए खाद्य उत्पाद से नैचुरल शब्द हटाने को कहा है। इसकी वजह उपभोक्ता रासायनिक युक्त उत्पाद के दुष्परिणामों के कारण नैचुरल एवं ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदने के लिए लालायित होते हैं। कई कंपनियां नैचुरल शब्द का प्रयोग कर उपभोक्ता को उनके उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करती हैं। अब से जो भी कंपनियां अपने उत्पाद में नैचुरल शब्द का प्रयोग करेगी तो उसे एफएसएसएआई के मानकों पर खरा उतरना होगा। कृषि उत्पादन में रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इससे मनुष्य को नुकसान हो रहा है। इससे जैवविविधता को भी नुकसान हो रहा है। रासायनिक खाद के उपयोग से जलाशय भी जहरीले हो रहे हैं। वर्ष 1965 तक देश में अक्सर खाद्यान्न की समस्या होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च उत्पादित एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के साथ रासायनिक खाद के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया। हरित क्रांति से देश को सफलता मिली एवं पैदावार बढ़ने से भारत कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भर बन गया। दूसरी और रासायनिक युक्त उत्पाद खाने से लोगों को अपने सेहत के साथ समझौता करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने इसके होने वाले दुष्परिणामों से देश को अवगत करा दिया था और साथ ही यह भी चेतावनी दी थी कि यह अल्पकालिक समाधान है, यह समाधान स्थायी नहीं हैं। देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस इस बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न की मांग की पूर्ति हेतु सरकार ने कभी रासायनिक खादों पर पाबंदी नहीं लगाई है। परिणामस्वरूप कृषि भूमि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक खाद से उत्पादित उत्पाद खाने से यकृत, गुर्दे और हृदय में नकारात्मक असर पड़ता है। इससे लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। इसलिए सरकार को रासायनिक खाद का विकल्प खोजना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करना जरूरी है

स्वास्थ्य पर सरकार का जोर

सरकार आम लोगों की सेहत दुरुस्त रखने के लिए आयुष्मान योजना के तहत 40 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र वर्ष 2020 तक स्थापित करेगी। बीमारी गरीब परिवार को काफी संकट में डाल देती है। दैनिक मजदूरी करने वाला मजदूर जिसे रोजाना के हिसाब से पैसे मिलते हैं अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है जो उसकी स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। बीमारी के कारण वह मजदूरी पर नहीं जा पाता और उस दिन की मजदूरी से वंचित रह जाता है। इलाज में काफी पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे में आयुष्मान योजना उस गरीब तबके के लिए वरदान साबित होगा। देश के सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन इसका सबूत देती है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा होता है जहां नि:शुल्क इलाज हो पाता है। निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च अधिक है जिससे गरीब तबका खर्च वहन नहीं कर सकता है। अत: आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।